

एशिया लो-कार्बन बिल्डिंग परिवर्तन (ALCBT) परियोजना

उत्तर प्रदेश | भारत



परियोजना स्थान	एशिया / भारत
परियोजना अवधि	अगस्त 2023 – अगस्त 2028
परियोजना वित्तपोषण	यूरो 1.93 करोड़ (भारत – यूरो 0.46 करोड़)
विषय	हरित निवेश, जलवायु कार्रवाई, हरित भवन, नीति
GGGI परियोजना कोड	ROA035

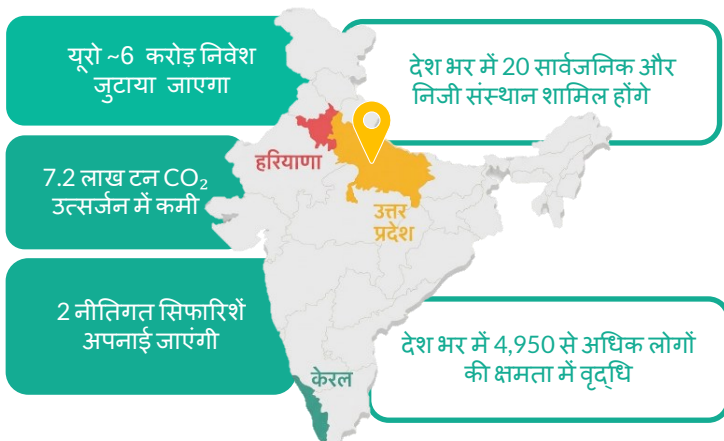
परियोजना का संक्षिप्त विवरण

भारत में विविध जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण भवनों में ऊर्जा उपयोग के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। भवन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त बनाने के भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप, एशिया लो-कार्बन बिल्डिंग परिवर्तन (Asia Low Carbon Buildings Transition – ALCBT) परियोजना भवनों में निहित और परिचालन कार्बन का आकलन करेगी। साथ ही, यह परियोजना ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code – ECBC) को व्यापक रूप से लागू करने में सहायता करेगी। उत्तर प्रदेश में कम-कार्बन भवनों की पहचान के लिए 600 भवनों का एक विस्तृत भवन अभिलेख (सूची) तैयार किया गया है। इनमें से 22 चयनित भवनों को ऊर्जा-कुशल और प्राकृतिक शीतलन उपायों के साथ उन्नत किया गया है।

यह परियोजना भारत में 4,950 से अधिक सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों, भवन विशेषज्ञों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों, ऊर्जा सेवा कंपनियों (Energy Service Companies – ESCOs), बैंकों और वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करेगी। साथ ही, यह भारत में कम-कार्बन परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए वित्त जुटाने में भी सहायता करेगी।

परियोजना का लक्ष्य और उद्देश्य

इस परियोजना का लक्ष्य देशभर में लो-कार्बन भवनों (Low Carbon Buildings – LCBs) की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य तकनीकी, नीतिगत और संस्थागत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होगी।



यह परियोजना भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) के मार्गदर्शन में केरल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

संघ भागीदार



राज्य सरकार के भागीदार



वित्तीय सहयोगी

Supported by:



based on a decision of the German Bundestag

समन्वयक मंत्रालय



Ministry of Housing
and Urban Affairs
Government of India



उत्तर प्रदेश अध्याय

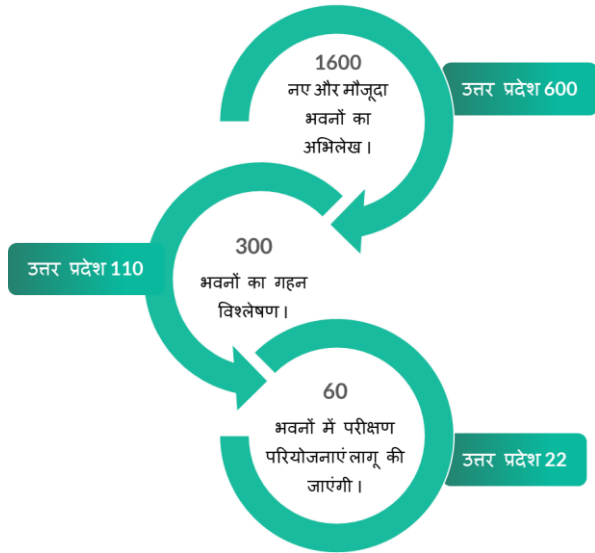
भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण शीतलन की बढ़ती आवश्यकता है। अनुमान है कि 2030 तक भवन क्षेत्र लगभग **85,000** करोड़ किलोवाट-घंटे (kWh) बिजली की खपत करेगा। 2030 तक भारत के भवन अवसंरचना का लगभग 70% हिस्सा अभी निर्मित होना बाकी है, जो कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan - ICAP) शीतलन की मांग को कम करने और ऊर्जा-कुशल भवनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

उत्तर प्रदेश में विविध जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं गर्मियों में उच्च तापमान और सर्दियों में निम्न तापमान, जिससे भवनों की ऊर्जा खपत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साथ ही, राज्य में तेजी से हो रहा शहरीकरण आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत अवसंरचना की बढ़ती मांग को बढ़ावा दे रहा है।

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (Global Green Growth Institute - GGGI), भारत-जर्मनी द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारत के तीन राज्यों में ALCBT परियोजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited - EESL) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment, Forest and Climate Change - DoEFCC) के साथ मिलकर इस परियोजना को मैं उत्तर प्रदेश कार्यान्वित किया जा रहा है।

भवन अभिलेख (Building Registry)

परियोजना के तहत 1,600 नए और मौजूदा भवनों का एक विस्तृत अभिलेख तैयार किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 600 भवनों का गहन विश्लेषण किया गया है।



भारत और उत्तर प्रदेश के भवन अभिलेख



Learn more at www.alcibt.gggi.org

#AsiaLowCarbonBuildings
#IndiaTowardsLCBT
#LowCarbonHighComfort

GGGI भारत
एम-6, तीसरी मंजिल, अरविंदो मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली 110016, भारत
ईमेल: india@gggi.org

GGGI मुख्यालय
19वीं मंजिल, जियोगडॉन्ग बिल्डिंग, 21-15
जियोगडॉन्ग-गिल, जुंग-गु, सियोल, कोरिया गणराज्य
04518 ईमेल: communications@gggi.org

उत्तर प्रदेश में परियोजना के अपेक्षित परिणाम

2028 तक, भारत में प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा 'लो कार्बन बिल्डिंग' (LCB) के लिए तकनीकी, नियोजन और संस्थागत उपकरण विकसित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाएंगे।

2.7 लाख टन उत्सर्जन में कमी



8 सार्वजनिक और निजी संस्थान LCBs से संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण अपनाएंगे



~1 नीतिगत सिफारिश अपनाई जाएगी



~2.2 करोड़ निवेश जुटाया जाएगा



22 भवनों में परीक्षण परियोजनाएं लागू की जाएंगी (प्राकृतिक शीतलन तकनीकों के साथ)



14 जुलाई 2025 को लखनऊ स्थित टैगोर मार्ग परिसर, आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग संकाय (Faculty of Architecture & Planning - FOAP), डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) में परियोजना का शुभारंभ।



तकनीकी सलाहकार समिति (TAC)की बैठक: नई दिल्ली, भारत, 30 जुलाई, 2024।

www.gggi.org

हमारी गतिविधियों से जुड़ें:

